



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102026-276860
CG-DL-E-06102026-276860

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 286]
No. 286]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 28, 2026/आश्विन 6, 1948
NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 28, 2026/ASVINA 6, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2026

सेतु मामला आईडी - AD/OI/057/2026

विषय: चीन जनवादी गणराज्य से पेनिसिलिन G और उसके लवण के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

फा. सं. 6/56/2026-DGTR.—1. फा. सं. 6/56/2026-DGTR: समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद “अधिनियम” कहा गया है) तथा समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद “पाटनरोधी नियमावली, 1995” कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, लाइफियस फार्मा प्राइवेट लिमिटेड (जिसे इसके बाद “आवेदक” कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद “प्राधिकारी” कहा गया है) के समक्ष चीन जनवादी गणराज्य (“चीन जन. गण.”) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पेनिसिलिन G और उसके लवण (जिसे इसके

बाद “विचाराधीन उत्पाद” अथवा “संबद्ध वस्तु” अथवा “पीयूसी” कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए आवेदन दायर किया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पाटित आयात घरेलू उद्योग की स्थापना में सारवान बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और उसने चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद पेनिसिलिन-G और उसके लवण हैं। पेनिसिलिन-G, जिसे बेंज़िलपेनिसिलिन के नाम से भी जाना जाता है, जीवाणुरोधी यौगिकों के पेनिसिलिन समूह से संबंधित एक बीटा-लैक्टम एंटीबायोटिक है। इसका रासायनिक नाम 6-(2-फेनिलएसीटामिडो) पेनिसिलैनिक एसिड है। वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ, पीयूसी में पेनिसिलिन-G के सभी रूप, ग्रेड, सामर्थ्य और सांद्रताएं तथा उसके लवण रूप शामिल हैं, चाहे वे फार्माकोपियल मानकों के अनुरूप हों अथवा नहीं, और चाहे ठोस रूप में हों अथवा द्रव रूप में।
4. संबद्ध वस्तु का उपयोग मुख्यतः सक्रिय औषधि घटकों के विनिर्माण के लिए प्रमुख प्रारंभिक सामग्री (“KSM”)/API के रूप में तथा निमोनिया, दंत संक्रमण, डिप्थीरिया और मेनिन्जाइटिस जैसे संवेदनशील सूक्ष्मजीवों से होने वाले जीवाणु संक्रमणों के उपचार हेतु तैयार खुराक फॉर्मूलेशनों में API के रूप में किया जाता है।
5. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के लिए मापन की इकाई मीट्रिक टन (MT) है।
6. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29, जिसका शीर्षक “कार्बनिक रसायन” है, के अंतर्गत शीर्ष 2941 “एंटीबायोटिक्स” और अधिक विशिष्ट रूप से उप-शीर्ष 2941 10 10 के अंतर्गत “पेनिसिलिन और उसके लवण” विवरण में वर्गीकृत है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
7. सभी हितबद्ध पक्षकारों को सलाह दी जाती है कि वे पीयूसी के दायरे और पीसीएन पद्धति, यदि कोई हो, पर अपनी टिप्पणियां उन सूचना-पत्रों के प्रेषण की तारीख से 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करें, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, आवेदन का अगोपनीय पाठ और संबंधित प्रश्नावली/प्रश्नावलियां ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों और संबद्ध देश के राजनयिक प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों को प्रेषित की गई हों।

ख. समान वस्तु

8. आवेदक ने कहा है कि उसके द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और चीन जनवादी गणराज्य से निर्यातित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उत्पाद और आयातित संबद्ध वस्तु भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, कार्यों एवं उपयोगों, मूल्य निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं; वे तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और उपभोक्ताओं द्वारा परस्पर विनिमेय रूप से उपयोग किए जाते हैं। अतः वर्तमान जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ, आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान “समान वस्तु” माना जा रहा है।

ग. संबद्ध देश

9. आवेदक ने चीन जन. गण. और हांगकांग से पाटन का आरोप लगाया था। तथापि, डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों की जांच पर जांच की अवधि के दौरान हांगकांग से संबद्ध वस्तु का कोई आयात नहीं पाया गया। तदनुसार, वर्तमान जांच के लिए संबद्ध देश चीन जन. गण. है।

घ. जांच की अवधि

10. आवेदक ने जांच की अवधि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक प्रस्तावित की है, जो 12 माह की अवधि है। प्राधिकारी ने जांच की अवधि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक मानी है। क्षति जांच अवधि में वित्त वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 तथा जांच की अवधि शामिल है।

ड. घरेलू उद्योग एवं उसकी स्थिति

11. आवेदन लाइफ़ायस फार्मा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने कहा है कि भारत में पीयूसी का कोई अन्य उत्पादक नहीं है और वह भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र पात्र उत्पादक है। आवेदक ने दावा किया है कि पूर्व में भारत में पेनिसिलिन G का विनिर्माण किया जाता था; तथापि, पाटित आयातों के निरंतर दबाव के कारण भारत का पेनिसिलिन G उद्योग पूर्णतः बंद हो गया था। आवेदक ने वित्त वर्ष 2024-25 में समान वस्तु का उत्पादन शुरू किया है।
12. आवेदक के अतिरिक्त, भारत में संबद्ध वस्तु का एक अन्य उत्पादक, अर्थात् विर्चो पेट्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड ("विर्चो"), है। आवेदक ने दावा किया है कि विर्चो ने भारत में संबद्ध वस्तु की उल्लेखनीय मात्रा का आयात किया है और तदनुसार उसे घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं माना जाना चाहिए। तथापि, प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ विर्चो को घरेलू उद्योग का हिस्सा माना है। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के दायरे में विर्चो को शामिल करने के बाद भी आवेदक पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के अनुसार प्रमुख अनुपात का प्रतिनिधित्व करता है। आवेदक ने यह भी कहा है कि उसने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है।
13. रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि आवेदक पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के अर्थ में घरेलू उद्योग है। आवेदन पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है।

च. कथित पाटन का आधार**i. चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य**

14. आवेदक ने चीन के अभिगम प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क) का उल्लेख करते हुए उस पर भरोसा किया है और दावा किया है कि चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए तथा चीन जन. गण. के उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के संबंध में उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं। जब तक चीन जन. गण. के उत्पादक यह प्रदर्शित नहीं करते कि बाजार अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थितियां विद्यमान हैं, तब तक उनका सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।
15. आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में पीयूसी की लागत और कीमत से संबंधित सूचना सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त, किसी तीसरे देश से अन्य देशों को निर्यात कीमतों से संबंधित सूचना भी उपलब्ध नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-1 का पैरा 7 किसी अन्य उचित आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण की अनुमति देता है। आवेदक ने किसी अन्य उचित आधार पर, अर्थात् घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर तथा बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों की युक्तिसंगत वृद्धि के साथ सामान्य मूल्य की गणना करने का प्रस्ताव किया है। तदनुसार, वर्तमान जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ, चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार किसी अन्य उचित आधार पर, अर्थात् घरेलू उद्योग की विधिवत समायोजित उत्पादन लागत के आधार पर तथा बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों और लाभ की युक्तिसंगत वृद्धि के साथ निर्धारित किया गया है।

ii. निर्यात कीमत

16. विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत का निर्धारण डीजीसीआईएंडएस के आयात आंकड़ों में रिपोर्ट की गई विचाराधीन उत्पाद की सीआईएफ कीमत को ध्यान में रखकर किया गया है। कारखाना-द्वार निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, बंदरगाह व्यय, कमीशन, बैंक प्रभार, ऋण लागत और अंतर्देशीय भाड़े के मद में समायोजन का दावा किया गया है।

iii. पाटन मार्जिन

17. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना-द्वार स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया यह स्थापित होता है कि चीन जन. गण. से आयातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन मार्जिन सकारात्मक है और न्यूनतम सीमा से अधिक है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि चीन जन. गण. के निर्यातकों द्वारा विचाराधीन उत्पाद का भारत के घरेलू बाजार में पाटन किया जा रहा है।

छ.क्षति और कारणात्मक संबंध

18. आवेदक ने दावा किया है कि वह एक अस्थापित उत्पादक है और चीन जन. गण. से पाटित आयात घरेलू उद्योग की स्थापना में सारवान बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। आवेदक ने दावा किया है कि वह अपने अपेक्षित निष्पादन के अनुरूप उत्पादन और बिक्री प्राप्त नहीं कर सका है। इसके अतिरिक्त, जांच की अवधि के दौरान भारत में पीयूसी की मांग की तुलना में क्षमता उपयोग कम है। आवेदक ने दावा किया है कि जांच की अवधि के दौरान उसका वास्तविक निष्पादन अपेक्षित निष्पादन से कम रहा है। इसके अतिरिक्त, चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु के आयात घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम कीमत पर भारत में प्रवेश कर रहे हैं। आवेदक को संबद्ध देश से पाटित आयातों के पहुंच मूल्य के अनुरूप अपनी कीमतें कम करने के लिए विवश होना पड़ा है। इसके अतिरिक्त, आवेदक जांच की अवधि के दौरान नकद हानि वहन कर रहा है और उसे संचित ऋणात्मक प्रतिफल प्राप्त हुए हैं।
19. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध आयातों की मात्रा न्यूनतम सीमा से अधिक है और जांच की अवधि के दौरान भारत में संबद्ध वस्तु के लगभग समस्त आयात चीन जन. गण. से हुए हैं। पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-II को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ मानते हैं कि घरेलू उद्योग की स्थापना में सारवान बाधा के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध हैं; संबद्ध आयातों का प्रतिकूल प्रभाव मुख्यतः घरेलू उद्योग के मात्रा और कीमत संबंधी मानकों पर उनके प्रभाव के माध्यम से परिलक्षित होता है, और कथित पाटन तथा ऐसी क्षति के बीच कारणात्मक संबंध भी विद्यमान है।

ज. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

20. आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर तथा चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की स्थापना में परिणामी सारवान बाधा और ऐसी क्षति तथा पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध के संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर संतुष्ट होने के पश्चात, अधिनियम की धारा 9क के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5 के अनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन के अस्तित्व, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की उपयुक्त राशि की सिफारिश करने के लिए पाटनरोधी जांच शुरू करते हैं, जो लगाए जाने पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।

21. आवेदक ने प्राधिकारी से पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 13 के अनुसार प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करने और अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करने का अनुरोध किया है। जांच के उपयुक्त चरण पर, यदि और जिस सीमा तक आवश्यक हो, इस पर विचार किया जाएगा तथा हितबद्ध पक्षकार इस अधिसूचना में निर्धारित समय सीमा के भीतर इस संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

झ. प्रक्रिया

22. वर्तमान जांच में पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

23. सभी हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल (<http://setu.dgtr.gov.in>) पर अपना पंजीकरण करना आवश्यक है। हितबद्ध पक्षकारों के सभी संचार और प्रस्तुतियां उनके पंजीकृत नाम तथा संगत मामला आईडी-AD/OI/057/2026 के अंतर्गत सेतु पोर्टल पर अपलोड की जाएंगी। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तुति का विवरणात्मक भाग खोज-योग्य PDF/MS-Word प्रारूप में तथा डेटा फाइलें MS-Excel प्रारूप में हों।
24. संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उसके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार तथा भारत में विचाराधीन उत्पाद से संबंधित ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को अलग से सूचित किया जा रहा है, ताकि वे इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमाओं के भीतर सभी संगत सूचना दायर कर सकें। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरुआत अधिसूचना, पाटनरोधी नियमावली, 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में निर्धारित रूप और तरीके से दायर की जानी चाहिए।
25. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमाओं के भीतर, इस जांच शुरुआत अधिसूचना, पाटनरोधी नियमावली, 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में निर्धारित रूप और तरीके से वर्तमान जांच से संबंधित प्रस्तुति कर सकता है।
26. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय प्रस्तुति करने वाले किसी पक्षकार को उसका अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराना आवश्यक है।
27. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.dgtr.gov.in और सेतु पोर्टल (<http://setu.dgtr.gov.in>) पर नियमित निगरानी रखें। हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे संबद्ध जांच में आगे के घटनाक्रम से अवगत रहने तथा प्रश्नावली प्रारूपों, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/बैठक की अनुसूची, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाओं और ऐसी अन्य सूचना के संबंध में समय-समय पर जारी की जाने वाली सूचनाओं से अवगत रहने के लिए डीजीटीआर की वेबसाइट (<http://dgtr.gov.in/>) को नियमित रूप से देखें।

ट. समय सीमा

28. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सेतु पोर्टल (<http://setu.dgtr.gov.in>) पर उनके पंजीकृत नाम तथा संगत मामला आईडी - AD/OI/057/2026 के अंतर्गत अपलोड की जानी चाहिए। प्रत्येक प्रस्तुति के दोनों पाठ, अर्थात् गोपनीय पाठ (CV) और अगोपनीय पाठ (NCV), आवेदन के अगोपनीय पाठ और संबंधित प्रश्नावली/प्रश्नावलियां, अन्य बातों के साथ, ज्ञात पक्षकारों और संबद्ध देश के राजनयिक प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों को प्रेषित किए जाने वाले सूचना-पत्रों के प्रेषण की तारीख से 37 दिनों के भीतर, पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार, संबंधित निर्धारित कॉलमों में अपलोड किए जाने चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना

प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण है, तो प्राधिकारी रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुसार अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं।

29. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) की सूचना दें और इस अधिसूचना में निर्धारित उपर्युक्त समय सीमा के भीतर केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से अपनी प्रश्नावली के उत्तर दायर करें।
30. पीयूसी/पीसीएन पद्धति के दायरे पर टिप्पणियां दायर करने की 15 दिन की अवधि इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के साथ-साथ चलेगी।
31. पीयूसी/पीसीएन में संशोधन के कारण समय विस्तार: यदि प्राधिकारी किसी बाद की सूचना के माध्यम से पीयूसी और पीसीएन में ऐसा संशोधन करते हैं जो पहले प्रस्तावित नहीं था अथवा जांच शुरुआत अधिसूचना से भिन्न है, तो 15 दिनों का समय विस्तार दिया जाएगा। 15 दिनों का यह विस्तार संशोधित पीयूसी और पीसीएन संबंधी ऐसी अधिसूचना की तारीख से दिया जाएगा। इस पैरा में उल्लिखित 15 दिनों का समय विस्तार उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां जांच शुरू होने के बाद पीयूसी और पीसीएन पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया हो। 15 दिनों के समय विस्तार (यदि दिया गया हो) से अधिक समय के लिए आगे के विस्तार के अनुरोधों पर, पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुरूप, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर सामान्यतः विचार नहीं किया जाएगा।
32. समय विस्तार का कोई भी अनुरोध संबंधित पक्षकारों द्वारा मूल समय सीमा से कम से कम एक दिन पहले सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके बाद प्रस्तुत अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

33. वर्तमान जांच में जहां कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय प्रस्तुति करता है अथवा गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करता है, वहां ऐसे पक्षकार को पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 7(2) और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय पाठ साथ-साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपर्युक्त का अनुपालन न करने पर उत्तर/प्रस्तुति अस्वीकार की जा सकती है।
34. प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नावली के उत्तरों सहित कोई भी प्रस्तुति (उसके साथ संलग्न परिशिष्टों/अनुबंधों सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय पाठ अलग-अलग दायर करना आवश्यक है।
35. ऐसी प्रस्तुतियों के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर “गोपनीय” अथवा “अगोपनीय” स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी के समक्ष की गई कोई भी प्रस्तुति प्राधिकारी द्वारा “अगोपनीय” सूचना मानी जाएगी और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी प्रस्तुतियों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
36. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वभावतः गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना, जिसके संबंध में सूचना का आपूर्तिकर्ता गोपनीयता का दावा करता है। स्वभावतः गोपनीय होने का दावा की गई सूचना अथवा अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में, सूचना के आपूर्तिकर्ता को दी गई सूचना के साथ यह बताते हुए उचित कारण का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता।
37. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर सूचना का अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय सूचना को अधिमानतः सूचकांकित किया जाए अथवा, जहां सूचकांकन संभव न हो, रिक्त किया जाए; और जिस सूचना पर गोपनीयता का दावा किया गया है उसकी प्रकृति के अनुसार ऐसी सूचना का उचित एवं पर्याप्त सार प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

38. अगोपनीय सार में इतना पर्याप्त विवरण होना चाहिए कि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना के सारतत्त्व को युक्तिसंगत रूप से समझा जा सके। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह संकेत कर सकता है कि ऐसी सूचना का सार प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है; ऐसी स्थिति में पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 7 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त एवं समुचित स्पष्टीकरण वाला कारणों का विवरण, कि ऐसा सार प्रस्तुत करना क्यों संभव नहीं है, प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
39. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय पाठ के परिसंचरण की तारीख से 7 दिनों के भीतर गोपनीयता से संबंधित मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।
40. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जांच करने के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है, अथवा सूचना का आपूर्तिकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत अथवा सार रूप में उसके प्रकटन को अधिकृत करने के लिए इच्छुक नहीं है, तो प्राधिकारी ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं।
41. जिस प्रस्तुति के साथ उसका सार्थक अगोपनीय पाठ अथवा गोपनीयता के दावे के संबंध में पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त एवं समुचित कारण का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया हो, उसे प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

42. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा की गई प्रस्तुतियों के सभी अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉग-इन के माध्यम से उपलब्ध होंगे।

ढ. असहयोग

43. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना तक पहुंच देने से इंकार करता है या अन्यथा उचित अवधि के भीतर अथवा इस जांच शुरुआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराता है, अथवा जांच में उल्लेखनीय रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं, रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं तथा केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं जिन्हें वे उचित समझें।

अमिताभ कुमार, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th September, 2026

SETU CASE ID - AD/OI/057/2026

Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of “Penicillin G and its salts” from the People’s Republic of China.

F. No. 6/56/2026-DGTR.—1. Having regards to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as the ‘Act’) and the Customs Tariff (Identification, Assessment, and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the ‘AD Rules, 1995’), Lyfius Pharma Private Limited (hereinafter referred to as the ‘applicant’) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the ‘Authority’), for initiation of an anti-dumping investigation on imports of Penicillin G and its salts (hereinafter referred to as the ‘product under consideration’ or the ‘subject goods’ or the ‘PUC’), originating in or exported from the People’s Republic of China (“China PR”).

2. The applicant has alleged that dumped imports originating in or exported from the China PR is causing material retardation to the establishment of the domestic industry and has requested for the imposition of anti-dumping duties on the imports of the subject goods from China PR.

A. Product under consideration

3. The product under consideration in the present investigation is Penicillin-G and its salts. Penicillin-G, also known as benzylpenicillin, is a beta-lactam antibiotic belonging to the penicillin group of antibacterial compounds. Its chemical name is 6-(2-phenylacetamido)penicillanic acid. For the purposes of the present investigation, the PUC includes Penicillin-G in all forms, grades, strengths and concentrations, along with its salt forms, whether or not conforming to pharmacopeial standards, and in both solid and liquid form.
4. The subject goods are principally used as a key starting material (“KSM”)/API for the manufacture of active pharmaceutical ingredients, and as an API in finished dosage formulations for the treatment of bacterial infections caused by susceptible organisms, such as pneumonia, dental infections, diphtheria and meningitis.
5. The unit of measurement considered in the present investigation for the product under consideration is Metric Tonnes (MT).
6. The product under consideration is classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975 titled “Organic Chemicals”, under heading 2941 “Antibiotics”, and more specifically under sub-heading 2941 10 10 under the description “Penicillins and its salts”. The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the present investigation.
7. All interested parties are advised to furnish their comments on the scope of the PUC and the PCN methodology, if any, within 15 days from the date of transmission of the intimation letters, containing, *inter alia*, the non-confidential version of the application and the respective questionnaire(s), to the known interested parties and the diplomatic representative(s) of the subject country.

B. Like article

8. The applicant has stated that there are no known differences between the subject goods produced by the applicant and those exported from the People’s Republic of China. The domestic product and the imported subject goods are comparable in terms of physical and chemical characteristics, functions and uses, pricing, distribution and marketing, and tariff classification; they are technically and commercially substitutable and are used interchangeably by consumers. Thus, for the purpose of initiation of the present investigation, the subject goods produced by the applicant are being treated as ‘like article’ to the product under consideration imported from the subject countries.

C. Subject country

9. The applicant had alleged dumping from China PR and Hong Kong. However, upon examination of DGCI&S data, no imports of subject goods from Hong Kong were found during the POI. Accordingly, the subject country for the present investigation is China PR.

D. Period of investigation

10. The applicant has proposed the period of investigation as 1st April 2025 to 31st March 2026, which is a period of 12 months. The Authority has considered the period of investigation as 1st April 2025 to 31st March 2026. The injury investigation period covers the financial years 2022-23, 2023-24, 2024-25 and the period of investigation.

E. Domestic industry and standing

11. The application has been filed by Lyfius Pharma Private Limited. The applicant has stated that there are no other producers of the PUC in India and that it is the sole eligible producer of the subject goods in India. The applicant has claimed that previously Penicillin G was manufactured in India, however, due to continuous onslaught of dumped imports, Indian Penicillin G industry was completely shut down. The applicant has commenced production of the like article in FY 2024-25.
12. Apart from the applicant, there is one other producer, namely Virchow Petrochemicals Private Limited ("Virchow"), of subject goods in India. The applicant has claimed that Virchow has imported significant quantities of subject goods in India and accordingly, should not be considered as part of the domestic industry. The Authority, however, for the purpose of initiation has considered Virchow as part of the domestic industry. The Authority further notes that even after inclusion of Virchow within the scope of the domestic industry, the applicant constitutes major proportion in terms of Rule 2(b) of AD Rules, 1995. The applicant has also stated that it has not imported the subject goods during the POI.
13. Based on information available on record, the Authority is satisfied that the applicant constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of AD Rules, 1995. The application satisfies the requirements of standing in terms of Rule 5(3) of AD Rules, 1995.

F. Basis of alleged dumping**i. Normal value for China PR**

14. The applicant has cited and relied upon Article 15(a) of China's Accession Protocol and has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and that producers from China PR should be directed to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry with regard to the production and sales of the product under consideration. Unless the producers from China PR show that such market economy conditions prevail, their normal value should be determined in accordance with paragraphs 7 and 8 of Annexure-I to the AD Rules, 1995.
15. The applicant has submitted that information relating to the cost and price of the PUC in a market economy third country is not available in the public domain. Further, information pertaining to export prices from a third country to other countries is also not available. The Authority notes that paragraph 7 of Annexure I of AD Rules, 1995 permits determination of normal value on any other reasonable basis. The applicant has proposed to compute normal value based on any other reasonable basis i.e., based on the cost of production of the domestic industry and with reasonable addition of selling, general and administrative expenses. Accordingly, for the purposes of present initiation, normal value for China PR has been determined on any other reasonable basis in terms of Para 7 of Annexure-I, i.e., on the basis of domestic industry's cost of production, duly adjusted, with a reasonable addition for selling, general and administrative expenses and profit.

ii. Export price

16. The export price of the product under consideration has been determined by considering the CIF price of the product under consideration as reported DGCI&S import data. Adjustments have been claimed on account of ocean freight, ocean insurance, port expenses, commission, bank charges, credit cost and inland freight to arrive at the ex-factory export price.

iii. Dumping margin

17. The normal value and export price have been compared at the ex-factory level, which *prima facie* establishes that the dumping margin in respect of the product under consideration imported from China PR is positive and above the *de minimis* level. There is sufficient *prima facie* evidence that the product under consideration is being dumped into the domestic market of India by exporters from China PR.

G. Injury and causal link

18. The applicant has claimed that it is an unestablished producer and that dumped imports from China PR are materially retarding the establishment of the domestic industry. The applicant has claimed that it has not been able to achieve production and sales as per its expected performance. Further, capacity utilisation is low in relation to the demand for the PUC in India during the POI. The applicant has claimed that their actual performance during the POI falls short of the expected performance. Further, subject imports from China PR are entering into India below the cost of sales of the domestic industry. The applicant has been forced to reduce its prices to match the

landed price of dumped imports from the subject countries. Moreover, the applicant is incurring cash losses and has accumulated negative returns during the POI.

19. The Authority notes that the volume of the subject imports is above *de minimis*, with China PR accounting for virtually the entire imports of the subject goods into India during the period of investigation. Having regard to Annexure II to the AD Rules, 1995, the Authority considers, for the purpose of initiation, that there is sufficient *prima facie* evidence of material retardation to the establishment of the domestic industry, the adverse effect of the subject imports being manifested principally through their effect on the volume and price parameters of the domestic industry, and of a causal link between the alleged dumping and such injury.

H. Initiation of anti-dumping investigation

20. On the basis of the duly substantiated written application submitted by the applicant and having reached satisfaction based on the *prima facie* evidence submitted by the applicant concerning the dumping of the product under consideration originating in or exported from China PR, the consequential material retardation to the establishment of the domestic industry as a result of the alleged dumping of the product under consideration and the causal link between such injury and the dumped imports, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the AD Rules 1995, the Authority, hereby, initiates an anti-dumping investigation to determine the existence, degree, and effect of the dumping with respect to the product under consideration originating in or exported from China PR and to recommend the appropriate amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.
21. The applicant has requested the Authority to issue preliminary findings and to recommend imposition of provisional anti-dumping duty in terms of Rule 13 of the AD Rules, 1995. The same shall be considered, if and to the extent warranted, at the appropriate stage of the investigation, and the interested parties may furnish their comments thereon within the time limit prescribed in this notification.

I. Procedure

22. The provisions stipulated in Rule 6 of the AD Rules, 1995 shall be followed in this investigation.

J. Submission of information

23. All the interested parties are required to register themselves on SETU Portal (<http://setu.dgtr.gov.in>). All communications and submissions from the interested parties shall be uploaded on the SETU portal under their registered name and corresponding case ID-AD/OI/057/2026. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.
24. The known producers/exporters in the subject countries, the government of the subject countries through their Embassy in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the product under consideration are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the AD Rules, 1995 and the applicable trade notices issued by the Authority.
25. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the AD Rules, 1995 and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.
26. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make available a nonconfidential version of the same to the other interested parties.
27. The interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of Directorate General of Trade Remedies at www.dgtr.gov.in and SETU portal (<http://setu.dgtr.gov.in>) for any updated information with respect to this investigation. Interested parties are directed to regularly visit the website of the DGTR (<http://dgtr.gov.in/>) to stay apprised with the further developments in the subject investigation and remain informed regarding notices that may be issued from time to time regarding questionnaire formats, PCN methodology, PCN discussion/meeting schedule, notice of oral hearing, corrigendum, amendment notifications and other such information.

K. Time limit

28. Any information relating to the present investigation must be uploaded by the interested parties on the SETU portal (<http://setu.dgtr.gov.in>) under their registered name and corresponding case ID - AD/OI/057/2026. Both version of each submission, the confidential version (CV) and the non-confidential version (NCV) must be uploaded in the respective designated columns **within 37 days** from the date of transmission of the intimation letters, containing, inter alia, the non-confidential version of the application and the respective questionnaire(s), to the known parties and the diplomatic representative(s) of the subject countries as per Rule 6(4) of the AD Rules, 1995. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete,

the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the AD Rules, 1995.

29. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification through SETU portal only.
30. The 15-day period to file comments on the scope of the PUC/PCN Methodology shall run concurrently with the time limit mentioned in this initiation notification.
31. Extension due to Modification of PUC/PCN: An extension of time by 15 days shall be granted if the Authority, through a subsequent notice, modifies the PUC and PCN that was not previously proposed or is different from the initiation notification. The extension of 15 days shall be granted from date of such notification of modified PUC and PCN. Extension of time by 15 days stated in this paragraph is not applicable in instances where there is no change in the PUC and PCN methodology, after initiation of investigation. Requests for a further extension of time, beyond the 15 days extension (if granted), will ordinarily not be considered except in case of exceptional circumstances, in line with the Rules 6(4) of the AD Rules, 1995.
32. Any request for an extension must be submitted by the concerned parties through the SETU portal at least one day before the original deadline. Requests submitted after this time will not be considered.

L. Submission of information on confidential basis

33. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the AD Rules, 1995 and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.
34. The parties making any submission (including Appendices/Annexes attached thereto), before the Authority including questionnaire responses, are required to file confidential and non-confidential versions separately.
35. Such submissions must be clearly marked as 'confidential' or 'non-confidential' at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as 'non-confidential' information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.
36. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
37. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
38. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the AD Rules, 1995, and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
39. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents.
40. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
41. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the AD Rules, 1995 and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

M. Inspection of public file

42. All non-confidential versions of submissions made by any interested party will be accessible to other interested parties through their respective login on the SETU Portal.

N. Non-cooperation

43. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

AMITABH KUMAR, Designated Authority